वाना में नई कूटनीतियों और गठबंधनों का युग

डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी*

अरब जगत के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में अरब क्रांति की पैठ के चार वर्ष बीत चुके हैं। इसके (आगमन के) बाद इसके प्रभाव का विश्लेषण विभिन्न समीक्षकों द्वारा अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से किया गया है। इस राजनीतिक उथल-पुथल को प्रदर्शित करने के लिए जिस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, उसे अरब शिशिर से लेकर अरब शरद तक कहा गया क्योंकि इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए।

वर्तमान उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में जो कुछ नजर आ रहा है, वह कुछ देशों में सत्ता के विघटन, कुछ अन्य राष्ट्रों में सत्ता संघर्ष और इस सम्पूर्ण क्षेत्र के भू-राजनीतिक वातावरण को नष्ट कर रहे कट्टरपंथी सिपहसलारों/सरदारों के आविर्भाव का मिला-जुला स्वरूप मात्र है। इतना ही नहीं, बल्कि जारी अंतरा-क्षेत्रीय संघर्ष इस क्षेत्र के सामरिक मानचित्र में तेजी से हो रहे स्थिति स्पष्टीकरण में भी सहायक है। इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के भिन्न-भिन्न आयाम हैं, जिन्हें क्षेत्र-पार और आंतरिक सांप्रदायिक मतभेदों में विभाजित किया जा सकता है।

इस क्षेत्र में अमरीका की चुनौतीमुक्त भूमिका में परिवर्तन के संबंध में अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में उदासीनता के लंबे चरण के बाद रूस का कूटनीतिक दावा एक सच्चाई है और यह तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम वहां अमरीका की उपस्थिति के दो दशकों का मूल्यांकन करते हैं।

यह भविष्य ही बताएगा कि यदि ईरान और अमरीका दोनों आगे बढ़कर अत्यंत विवादास्पद परमाणु सौदे को हथिया लेते हैं, तब अमरीका इस क्षेत्र में ईरान-अभिप्रेरित सक्रिय गुट के साथ कैसे पेश

आएगा, क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के (सदस्य) राष्ट्र इस क्षेत्र में ईरान के इरादे और परमाणु-पश्चात सौदेबाजी की रूपरेखा के बारे में पहले ही बेचैनी का प्रदर्शन कर चुके हैं। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के (सदस्य) राष्ट्र भविष्य में अमरीका की प्रतिबद्धता के प्रति सशंकित हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने अमरीका पर बार-बार इस क्षेत्र में कमजोर नीति का अनुसरण करने का आरोप लगाया है, विशेषकर सीरिया के राष्ट्रपति असद के विरूद्ध, जो ईरान के रणनीतिक सहयोगी और सऊदी अरब के साम्प्रदायिक विस्तार के सामने मजबूत दीवार हैं। शेख अबदुल्ला के निधन के साथ ही अमरीका तथा अन्य क्षेत्रीय राष्ट्र इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि सऊदी अरब शेख सुलेमान के नए शासन के तहत अपनी क्षेत्रीय नीतियों का खुलासा कैसे करता है।

ईरान के साथ-साथ असद की शासन व्यवस्था को रूस का लगातार राजनीतिक तथा संभारतंत्रीय समर्थन इसकी बढ़ती भूमिका का द्योतक है। इतना ही नहीं, रूस तथा मिस्र के बीच सिकंदरिया पत्तन में नौसैनिक सहयोग हेतु तीन अरब अमरीकी डॉलर के रक्षा सौदे तथा करार दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता को प्रतिबिंबित करते हैं जो 1970 के दशक के मध्य में मिस्र के अचानक अमरीकी खेमे में चले जाने के पश्चात् उनके बीच तीन दशकों के अलगाव को देखते हुए एक बड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है। वर्ष 2012 में रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन का इज़राइल दौरा इज़राइल के भंडार से गैस निकालने संबंधी सौदे के साथ संपन्न होना एक और पहलू है जो इस क्षेत्र में रूस की बढ़ती भूमिका के बारे में बताता है। सीरिया जैसे लेवान्त क्षेत्र और मिस्र जैसे उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में रूस की बढ़ती भूमिका को कुछ क्षेत्रीय गठबंधनों के उभरने से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके साम्प्रदायिक और कट्टरपंथी आयाम हैं।

सीरिया में लोकतंत्र-समर्थक विरोध प्रदर्शन ने एक साम्प्रदायिक असैनिक संघर्ष का रूप ले लिया जिसने इस देश को दो परम्परागत क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वियों ईरान तथा सऊदी अरब के बीच छद्म युद्ध के केन्द्र में बदल दिया। इस छद्म युद्ध ने ईरान को तेहरान से लेबनान तक अपने लिए अर्ध-चन्द्राकार क्षेत्र का विस्तार करने में सीरिया, लेबनान के हजबुल्ला और इराक के शिया-समर्थक शासन के सुदृढ़ समर्थन के आधार पर इस क्षेत्र में अपने लिए एक नई कूटनीतिक भूमिका प्राप्त करने में सफल बना दिया। ऐसे पांच अलग-अलग समूह (शासन-व्यवस्था, ईरान, उदारवादी विपक्ष, विभिन्न मिलिशिया तथा ज़िहादी और कुर्द) हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम बना रखा है। ईरान ने अपने साम्प्रदायिक गढ़ों की रक्षा करने का कदम उठाया तथा यह इस क्षेत्र में निर्विवाद कूटनीतिक कार्यकर्ता/राष्ट्र बनने के लिए सऊदी के नेतृत्व वाले 'उदारवादी' गठबंधन को प्रतिस्थापित करने में अपनी क्षेत्रीय भूमिका सावधानीपूर्वक निभा रहा है। अब ईरान ने सीरिया के भविष्य के बारे में होनेवाली किसी भी वार्ता में अपने लिए एक स्थान सुरक्षित कर लिया है।

ईरान-प्रेरित गठबंधन ने सऊदी अरब, बहरीन और यमन जैसे अन्य देशों के शिया समूहों के समर्थन के साथ-साथ रूस का पर्याप्त राजनीतिक तथा संभारतंत्रीय समर्थन जुटा लिया है। यमन में राजधानी शहर सना पर यमनी हाउती विद्रोहियों का पूर्ण नियंत्रण तथा इसके बाद इसके राष्ट्रपति का त्यागपत्र सऊदी शासन व्यवस्था के लिए आईएसआईएस से भी बड़ा खतरा प्रतीत होता है क्योंकि इसके कारण सऊदी अरब इस क्षेत्र में अपने एतिहासिक सहयोगियों में से एक (यमन) को खो सकता है। सऊदी सरकार पहले ही ईरान पर बहरीन के शिया-बहुल अधिराज्य के साथ एक नया परिसंघ बनाने हेतु इस अधिराज्य से पृथक होने के लिए शिया समूहों को उकसाकर इसके पूर्वी प्रान्त में सांप्रदायिक युद्ध प्रारंभ कराने का आरोप लगाती रही है।

ईरान-प्रेरित गठबंधन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, इसका परंपरागत प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब, मिस्र के रूप में एक नए कूटनीतिक सहयोगी के साथ इस क्षेत्र में ईरानी ज्वार को रोकने के लिए अपने पास मौजूद सभी कूटनीतिक साधनों का उपयोग कर रहा है। पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों में जातीय/सांप्रदायिक युद्ध के सूत्रपात के बाद से सऊदी अरब सद्दाम हुसैन के प्रस्थान के बाद के इराक में सुन्नी शासन को हुई हानि की भरपाई करने हेतु शिया समूह के कूटनीतिक स्तंभ को कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति असद को हटाने की जोरदार वकालत कर रहा है।

सऊदी-अमरीका संबंधों का मजबूत आधार तब कमजोर होता प्रतीत हुआ, जब अमरीका ने वर्ष 2011 के प्रारंभ में मिस्र में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति मुबारक का साथ छोड़ दिया; जिससे दोनों (देशों) के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो गया और निश्चित रूप से अमरीका को इस अधिराज्य की सद्भावना अब उस हद तक नहीं मिल रही है जितनी अतीत में मिलती थी। बेशक, परमाणु वार्ता की घोषणा के बाद ईरान और अमरीका के बीच बढ़ती निकटता और आगे चलकर आईएसआईएस के विरूद्ध स्पष्ट समझ ने अमरीका और सऊदी अरब के बीच राजनैतिक उदासीनता को और गहरा कर दिया है। इस क्षेत्र में सऊदी के प्रभाव को और सुदृढ़ करने हेतु एकीकृत रक्षा कमांड (यूडीसी) स्थापित करने के लिए पिछले खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) शिखर सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के अलावा, मिस्र, मोरक्को और जॉर्डन शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब चाहता है कि कतर और कुवैत जैसे अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) सदस्यों को नाराज न करने के इरादे के साथ मिस्र एक पूर्ववर्ती कार्यवाही के रूप में संयुक्त कमांड का नेतृत्व करे, जो इस अधिराज्य के नेतृत्व पर अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। साम्प्रदायिक गठबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए ओमान और कुवैत की मध्यस्थता में सऊदी अरब और कतर के बीच हाल ही में एक समझौता

किया गया है, जब अरब क्रान्ति के बाद उनके बीच संबंधों में कडवाहट आ गई।

ईरान और सऊदी अरब के अलावा, इस क्षेत्र में अन्य राष्ट्र भी अपने रणनीतिक गणित के अनुसार साम्प्रदायिक लड़ाकों को सभी प्रकार का कूटनीतिक समर्थन भी प्रदान कर रहे हैं। इस बीच, कट्टरपंथियों, अतिवादियों और आतंकवादी समूहों के साथ-साथ 'स्ट्रीट जिहादी' नाम के अनेक उपद्रवियों का उभरना एक और दुखद परिणाम है, जिसके बारे में आज मानना पड़ता है कि खुद "अरब क्रांति" के रूप में पहले हुई राजनैतिक उथल-पुथल की न्यूनीकारक परिभाषा अत्यंत त्रुटिपूर्ण और जल्दीबाजी में दी गई उपाधि थी। सिपहसलारों और जिहादियों का यह विचित्र समूह न केवल इस क्षेत्र के भू-रणनीतिक बल्कि भौगोलिक मानचित्र को भी बदलने पर पूर्णतया उतारू है। इन सबमें सबसे प्रमुख आईएसआईएस रहा है। यह इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिखरे *जिहादियों* का ध्रुवीकरण करने में सफल रहा है, जो उनमें शामिल होने के लिए अपने पैतृक संगठनों को अलविदा कह रहे हैं। गहराती सत्ताशून्यता के कारण सीरिया और इराक उनके लिए उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं। आईएसआईएस के तेज विस्तार ने अनेक देशों को इसके उत्कर्ष/उत्थान का सामना करने के लिए अपने रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है। उदाहरण के लिए, इसने तुर्की और ईरान दोनों को अपने पूर्व राजनीतिक रूखों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि आईएसआईएस के उत्थान ने इस क्षेत्र में भू-रणनीतिक जटिलताओं को गहरा दिया है। इसने तुर्की को अपनी विदेश नीति के आधार को बदलने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आईएसआईएस इसके सीमा प्रान्त के अत्यंत निकट पहुंच गया है और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इराकी कुर्दों के साथ आईएसआईएस की भागीदारी के कारण कुर्दिश राजनीतिक आंदोलन के प्रति तुर्की की नीति भी निकट भविष्य में पुन:निर्धारित होने की संभावना है। आईएसआईएस ने अमरीका को भी आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में फिर से शामिल होने पर मजबूर कर दिया है, जबकि यह 'आतंक से युद्ध' का अपना अभियान समाप्त कर चुका था। इतना ही नहीं, आईएसआईएस के खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए ईरान और अमरीका के बीच गुप्त वार्ताएं चलने की अपुष्ट खबरें भी मिल रही हैं। तथापि, यह अभी भी पहेली बनी हुई है कि 3000 से भी कम (व्यक्तियों) का एक समूह कैसे इतने कम समय में सीरिया और इराक में बड़े भूभाग पर कब्जा करने में समर्थ हो गया और इसके पनपने को लेकर कूटनीतिक समुदाय को अरब जगत में आतंकवाद के संदर्भित वंशावली की नए सिरे से परिभाषा तथा व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

यह न केवल सिपहसलार/सरदार हैं जो इस क्षेत्र के कुछ भागों की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा

पैदा कर रहे हैं, बल्कि यमन और लीबिया जैसे देश तो राष्ट्रविहीन हो गए हैं। उदाहरण के लिए, यमन की राजधानी सना पूरी तरह से "हाउती" विद्रोहियों के नियंत्रण में है और इसके राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। ऐसी ख़बर मिली है कि हाउतियों ने यमनी राष्ट्रीय सेना के लगभग 70 प्रतिशत हथियार पर कब्जा कर लिया है और लम्बी दूरी की मिसाइलें, टैंक और सशस्त्र वाहन जैसे सभी अत्याधुनिक हथियार उनके कब्जे में है।

इसी प्रकार, कर्नल गद्दाफी के तख्तापलट और बाद में नाटो-समर्थक अभियान में मारे जाने के तीन से अधिक वर्षों के बाद, अब भी लीबिया में हथियारों की बाढ़ सी आई हुई है और *फज्र लीबिया* तथा *शबाब-इस्लामी* जैसे लड़ाकों के विभिन्न गुट, अनेक बेदूइन जनजातीय ताक़तें और सिपाहसलार इस राष्ट्र को पूर्ण आरजकता की ओर धकेल रहे हैं और इसकी शासन प्रणाली का ध्वस्त होना अवश्यंभावी प्रतीत होता है। आज, लीबिया में एक समानान्तर संसद और सरकार है और परम्परागत सामाजिक तथा जनजातीय गठबंधन भी वर्तमान राजनीतिक संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल होती जा रही है।

इस क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, किसी भी प्रकार की राजनीतिक राय अथवा भविष्यवाणी कठिन प्रतीत होती है, लेकिन इस पड़ाव पर यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या सिपाहसलार, कट्टर समूह तथा सत्ता प्रतिद्वन्द्विता राष्ट्रीय सीमा का फिर से सीमांकन करेंगे अथवा बेचैनी, संघर्ष तथा अव्यवस्था के लम्बे दौर के बाद शांति, व्यवस्था तथा शासन पुन: बहाल होगा?

**डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*